शम्सुद्दीन और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

18 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति दोराईस्वामी राजू और न्यायाधिपति अरिजीत पासायत]

दंड संहिता, 1860- धारा 34 के साथ पठित धारा 302,307- सामूहिक वैमनस्य जिसके कारण अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरे को चोट पहुँचती है- विचारण न्यायालय द्वारा बरी किया जाना- उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि-सही- आयोजित किया - घायलों के साक्ष्य के साथ-साथ एफ. आई. आर. में भी कोई कमजोरी नहीं है- इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया गया है। सांप्रदायिक वैमनस्य के कारण अपीलार्थी-अभियुक्त ने आर और पीडब्लू-1 को चोट पहुँचाई, जिसके परिणामस्वरूप 'आर' की जान चली गई और पीडब्लू-1 गंभीर रूप से घायल हो गया। पीडब्लू-2 और पीडब्लू-8 ने इस घटना को देखा। पीडब्लू 2 ने पीडब्लू-1 के भाई को सूचित किया, जिसने इसके बाद एक प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज की। अपीलार्थी अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 302 और 307 के तहत आरोप लगाए गए थे। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला सबूतों द्वारा समर्थित नहीं था। उच्च न्यायालय

ने दोषमुक्ति किए जाने के फैसले को दरकिनार कर दिया, लेकिन यह माना कि अपीलार्थी धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी थे, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपीलार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि विचारण अदालत ने सबूतों का विश्लेषण किया था और दुर्बलताएं पाई थीं जो उच्च न्यायालय ध्यान देने में विफल रहा और अनुमानों के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया; कि पीडब्लू-1 का साक्ष्य आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है, वह पी.डब्ल्यू.-8 की उपस्थिति के बारे में बात नहीं करता है और उसके नाम का भी प्रथम इत्तला रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था और प्रथम इत्तला रिपोर्ट समय से पहले की गई थी और मनगढ़ंत थी।

प्रत्यर्थी-राज्य ने तर्क दिया कि उस व्यक्ति द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई थी जो एक प्रत्यक्षदर्शी था, कि हालाँकि पीडब्लू-1 से उस पर हमले के संबंध में व्यापक रूप से पूछताछ की गई थी, लेकिन मृतक पर हमलों के बारे में कोई सुझाव भी नहीं था; कि उच्च न्यायालय ने सावधानीपूर्वक पीडब्लू-1 के साक्ष्य का विश्लेषण किया और विश्वसनीय पाया गया; और यह कि उच्च न्यायालय ने विश्लेषण किया है कि कैसे याचिकाएं कि प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी या यह मनगढ़ंत थी, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से स्थापित नहीं हुई है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

पीडब्लू-1 का साक्ष्य किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। साक्ष्य के मूल को देखना होगा न कि किसी सीमा रेखा के पहलू को। मामूली भिन्नताएँ जिनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साक्ष्य के आंतरिक मूल्य को त्यागने का आधार नहीं हो सकता है। प्रथम इत्तला रिपोर्ट में पी. डब्ल्यू.8 के नाम की अनुपस्थिति का वास्तव में कोई महत्व नहीं है क्योंकि प्रथम इत्तला रिपोर्ट. पी. डब्ल्यू.1 के भाई द्वारा दर्ज की गई थी जो कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रथम इत्तला रिपोर्ट मनगढ़ंत नहीं थी, किसी भी विपरीत दृष्टिकोण से ग्रस्त नहीं है। इसके अलावा, जहां तक मृतक पर हमलों का संबंध है, पीडब्लू-1 की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा है कि घातक चोट स्पष्ट रूप से किसी विशेष आरोपी द्वारा नहीं दी गई थी, इस प्रकार यह मामला धारा 34 के आवेदन के साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत नहीं आता है। यह एक सही या तर्कसंगत और उचित दृष्टिकोण प्रतीत नहीं होता है। किसी भी स्थिति में, राज्य ने कोई अपील नहीं की है, और इसलिए, कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं है जो किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देता है। [1062 - जी-एच; 1063-ए-सी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 827/1997

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 7.1.97 के निर्णय और आदेश से आपराधिक अपील संख्या 299 /1992

अपीलार्थियों के लिए अनीस अहमद खान।

उत्तरदाता के लिए सिद्धार्थ दवे और सुश्री विभा दत्ता मखीजा।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति अरिजीत पासायत द्वारा दिया गया था :

साम्प्रदायिक उथल-पुथल ने भारी नुकसान किया है, कई लोग अलग-अलग समय पर जीते हैं। यह हमारे समाज पर एक दुखद प्रतिबिंब है, हालांकि भारत का संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') किसी भी अनिश्चित शब्दों में रेखांकित करता है कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां जाति, पंथ और धर्म का कोई विभेदक आधार नहीं ही सकता है। एक राजूनाथ (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) ने सांप्रदायिक वैमनस्य के कारण अपनी जान गंवा दी और दूसरे नरिश चंद्र (पीडब्लू-1) ने गंभीर रूप से घायल हो गए। अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध का रचिएता कहा गया था, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और 307 के तहत दंडनीय अपराध किए गए।

मुकदमे के दौरान अभियोजन संस्करण इस प्रकार हैः

दिनाक 21.10.1990 को दोपहर करीब 2:30 बजे अत्यधिक संवेदनशील कस्बे संधवा में सांप्रदायिक भावनाओं के कारण तनाव बढ़ रहा था। लगभग दोपहर में, दो समुदायों के बीच कुछ विवाद हुआ और उस विवाद में एक विशेष समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और यह

खबर दूर-दूर तक फैल गई। इसके बाद एक के बाद एक कई घटनाएं हुईं। बाजार के कुछ हिस्से बंद थे, कुछ प्रक्रिया में थे जब पुलिस बल ने कार्यवाही करना शुरू किया तो बंद कर दिया गया। पीडब्लू-1 नाई की दुकान चलाता है। उन्हें शास्त्री कॉलोनी के लिए रवाना होना था जो यहाँ से उसकी दुकान कुछ ही दूरी पर स्थित थी। मृतक भी उसी इलाके में रहता था। दोपहर करीब 2:30 बजे मृतक और पीडब्लू-1 अपनी दुकानें बंद करके घर लौट रहे थे। जब वे डाक बंगले के पास थे, तो अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध रूप से घायल करना शुरू कर दिया। घायल और मृतक ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और भागने लगे। मिट्ठू शर्मा (पीडब्लू-2) ने इस घटना को देखा और प्रेमचंद (पीडब्लू-8)। एक सत्यनारायन ने भी इस घटना को देखा। पीडब्लू 8 ने पीडब्लू-I के भाई संतोष (पीडब्लू-4) को सूचित किया, जो पुलिस स्टेशन गए और उनका बयान लगभग 2.45 बजे दर्ज किया गया। दोपहर करीब 2.00 बजे, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (संक्षेप में सी.आर. पी. सी.) को लागू किया गया था और तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने थोड़े समय के बाद कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। जाँच अधिकारी पीडब्लू-18 घटना स्थल पर पहुँचे और मृतक को और आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। दर्ज सूचना के आधार पर जांच की गई और आरोप पत्र दायर किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने निर्दोष होने का दावा किया। यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक का पोस्टमॉर्टम पीडब्लू-15 द्वारा किया गया था और पीडब्लू-16 ने घायल पीडब्लू-1 की जांच की थी। विचारण न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष

का बयान ठोस सबूतों द्वारा समर्थित नहीं था और तदनुसार बरी करने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी जिसने विवादित निर्णय द्वारा दोषमुक्ति के फैसले को दरकिनार कर दिया; लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि मामला आई. पी. सी. की धारा 302 के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि धारा 324 के अंतर्गत आता है और अभियुक्त को 2 साल के लिए आर. आई. से गुजरने और 2000 रुपए के जुर्माने का भुगतान करने की सजा सुनाई। यह भी निर्देश दिया गया कि राशि की वसूली के मामले में यही राशि मृतक की विधवा को दी जानी थी यदि वह विवाहित था, और यदि नहीं, तो उसके माता-पिता या उनमें से किसी जीवित व्यक्ति को दी जानी थी। 2,000 पीडब्लू-1 को देने का भी निर्देश दिया गया। यह ध्यान दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त व्यक्ति मृतक के साथ-साथ पीडब्लू-1 को चोट पहुँचाने के लिए आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचारण अदालत ने साक्ष्य का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया था और ऐसी दुर्बलताएँ पाई थीं जिन पर उच्च न्यायालय ध्यान देने में विफल रहा और अनुमानों पर अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पीडब्लू-1 का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। वह पीडब्लू-8 की उपस्थिति के बारे में बात नहीं करते हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व-समय पर तैयार की गई थी और मनगढ़ंत थी। यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि इसे अदालत में भेजा गया था।

जवाब में, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति द्वारा दर्ज नहीं की गई थी। हालाँकि पीडब्लू-1 से व्यापक रूप से पूछताछ की गई थी जहाँ तक उस पर हमले का संबंध था, मृतक पर हमलों के बारे में कोई सुझाव भी नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस बात का विश्लेषण किया है कि जिस समय प्रथम सूचना रिपोर्ट का दावा किया गया था, उस समय इसे दर्ज नहीं किया गया था या इसे गढ़ा गया था, यह याचिकाएं अभिलेख पर साक्ष्य द्वारा कैसे स्थापित नहीं की गई हैं। यदि किसी एक व्यक्ति का प्रमाण जिसके घायल होने का दावा किया जाता है वह विश्वसनीय और भरोसेमंद है, कानून में गवाहों की बहुलता पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ में होने के मामले में पीडब्लू-1 के साक्ष्य का उच्च न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया है और यह विश्वसनीय पाया गया है।

हमें यह नहीं बताया जा सका कि पीडब्लू-1 का साक्ष्य किसी भी दुर्बलता से कैसे पीड़ित है। साक्ष्य के मूल को देखना होगा न की किसी भी सीमा रेखा का पहलू को । मामूली भिन्नताएँ जिनका साक्ष्य की विश्वसनीयता कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे साक्ष्य के आंतरिक मूल्य को त्यागने का आधार नहीं हो सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडब्लू-8 के नाम की अनुपस्थिति का वास्तव में कोई परिणाम नहीं है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट पीडब्लू-4 द्वारा दर्ज की गई थी जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो गढ़ी नहीं गई थी, वह किसी भी विपरीत दृष्टिकोण से किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर जहाँ तक मृतक पर हमलों की बात है, व्यावहारिक रूप से पीडब्लू-1 से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई ।

ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय परिसर में आगे बढ़ा है क्योंकि चोट नं 6 जिसे घातक चोट कहा गया था, स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया गया था, किसी विशेष आरोपी द्वारा लगाया गया था, यह मामला धारा 34 के आवेदन के साथ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत नहीं आता है। हमारी राय में यह एक सही या तर्कसंगत और उचित दृष्टिकोण प्रतीत नहीं होता है। किसी भी स्थिति में, राज्य ने कोई अपील नहीं की है और इसलिए, हम उस मुद्धे पर कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझते हैं।हालांकि, उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं है जो किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी देता है। याचिका खारिज की जाती है। अभियुक्त व्यक्ति

अपनी शेष सजा, यदि कोई हो, पूरी करने के लिए हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा।

एन.जे.

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।